''स्वदेशी गोवंश की दूध उत्पादकता बढ़ाने हेतु रणनीति''

पर

आईसीएआर-एनएवीएस की विशेषज्ञ सलाहकार बैठक

अक्टूबर २०, २०१४ (सोमवार)

संकल्पना

मारे देश में लगभग 6.40 लाख से अधिक गांव हैं जहां 70 प्रतिशत जनता निवास करती है। ग्रामीण समुदाय में पशुपालन हमेशा से ही हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा रहा है। सीमांत, छोटे और मझौले पशुपालकों के पास विभिन्नि श्रेणी के 89 प्रतिशत गो वंश हैं। दूध, दूध उत्पादों, भारवाहक पशुओं, जैव—उर्वरक, जैव—ईंधन, जैव—कण बनाने तथा मानव स्वास्थ्य के लिए अन्य उपयोगी उत्पादों को तैयार करने में देशी गो वंशों का उपयोग होता है। इसके साथ ही ये भूमिहीन और संसाधन हीन किसानों के लिए उनकी आजीविका के स्रोत भी हैं।

18वीं पशु गणना (2007) के अनुसार, भारत में लगभग 199 मिलियन गोवंश की संख्या थी जिसमें से 166 मिलियन देशी (83%) तथा 33 मिलियन (17%) संकर और विदेशी नस्ल के गोवंश हैं। इस विशाल संख्या में से देशी गायों में से अब तक केवल 23.14 मिलियन (11.62 प्रतिशत) को वर्णित कर उन्हें 44 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है जिनमें से 37 विशिष्ट तथा पंजीकृत नस्लें हैं। देशी गोवंशीय नस्लों को सामान्यतः उनकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जैसे कि दुधारू नस्ल (साहिवाल, लालसिंधी, गिर एवं राठी), भार वाहक नस्ल (हलिकर, खिलर, नागौरी, कागयम, लाल कंधारी इत्यादि) तथा द्विउद्देश्यीय (दुधारू और भार वाहक) नस्लें (थारपरकर, हरियाणा, कांकरेज, देऊनी, अंगोल, डांगी, केंकथा आदि) शामिल हैं। पिछले 1,000 वर्ष से भी अधिक समय से पशुपालकों और चरावाहों के ठोस प्रयासों द्वारा ये नस्लें विकसित हुई हैं।

पिछले कुछ दशकों में, प्रजनन नीति में परिवर्तन तथा कुछ उन्नत विदेशी गौ नस्लों को अपनाने के कारण हमारे स्वदेशी गौ नस्लों की विशिष्ट जैव—विविधता में कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर देसी गायों से प्राप्त वर्तमान दूध उत्पादन मात्र 2.36 कि.ग्रा. प्रतिदिन है। इसके बावजूद, यह खास बात है कि दूध के अनुमानित (2013—14) राष्ट्रीय पूल में देसी गायों का 132.43 मिलियन टन का उल्लेखनीय योगदान रहा है। पिछले दशक में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में संचालित प्रयोगों से यह साबित होता है कि इन नस्लो ने अपने 305 दिन के दुग्धकाल में 2000—3500 लीटर तक दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता दिखाई है। क्योंकि अधिकांश राज्यों में गौ वंश की खेती के काम में आने वाली नस्लें हैं, अतः उनकी उत्पादकता में अल्प सुधार से ही देश के कुल दूध उत्पादन को बढ़ाने में सफलता मिल सकती है।















कांकरेज

साहिवाल

गिर

लालसिंधी

थारपरकर

राठी

खिल्लर

इसके अतिरिक्त, दूध उत्पादन ही वह अकेला मानदंड नहीं है जिसके आधार पर स्वदेशी गायों के महत्व का आकलन होना चाहिए। उनमें कई विशिष्ट —जीन पाए जाते हैं जो उच्च ताप सिहष्णुकता, तीव्र रोगों के प्रति बढ़ती प्रतिरोधिता तथा न्यूनतम लागत में बेहतर आहार परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही खेती तथा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में उनका योगदान अतुल्य है। इसके अलावा, हम इस तथ्य को भी नहीं नकार सकते कि भारतीय गौ वंश का कई अन्य प्रकार के उत्पादों में भी योगदान है जो मानव स्वास्थ्य के लिए औषधीय महत्व वाले पंचगव्य उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं।

अनुपयुक्त प्रजनन नीतियों तथा कुछ विदेशी नस्लों के प्रति उपभोक्ताओं की पसंद के कारण पिछले वर्षों में पशुओं की घटती हुई संख्या को देखते हुए स्वदेशी गाय के जर्मप्लाज्म का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। हमारे देश में पशु सुधार कार्यक्रमों में लगी हुई विभिन्न एजेंसियों के पास अच्छा बुनियादी ढांचा है। हमारे पास गैर सरकारी क्षेत्र 4000 से अधिक गौशालाएं हैं जिनमें लगभग 20 लाख देसी गायों का रखरखाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास 161 पशु प्रजनन फार्म, 54 वीर्य उत्पादन केन्द्र, 191 प्रशीतित वीर्य बैंक, 77,765 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, कई पशुचिकित्सा अस्पताल / पॉली—क्लीनिक तथा चिकित्सालय हैं। अधिकतर राज्यों में पशुपालन विभाग तथा पशुधन विकास बोर्ड गठित किए गए हैं। गैरसरकारी संगठन, प्रजनन एसोसिएशन, किसान समूह तथा चरवाहों जैसे सहयोगी भी देसी पशुओं की नस्लों के प्रजनन और संरक्षण में योगदान देते हैं।

इनमें से कई गौशालाएं उपयुक्त प्रजनन योजनाओं के द्वारा अपने संसाधनों के द्वारा भारतीय गौ वंश के संरक्षण में योगदान कर रही हैं। पशु पालन प्रक्रियाओं के बारे में हमारे पास प्राचीन परंपरागत ज्ञान का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। इनमें से कुछ ने मूल्यावर्धन तथा गोबर, मूत्र, सींग जैसे उत्पादकों के प्रयोग द्वारा इन आनुवंशिक संसाधनों की उपयोगिता को प्रदर्शित किया है। दूध एवम् दूध से बने पदार्थों के अतिरिक्त, दुर्भाग्य से कई गोशालाएं आदर्श अवस्था में नहीं हैं और उन्हें वित्तीय तथा तकनीकी सहायता की नितान्त आवश्यकता है।

नस्लों के सुधार और स्वदेशी गोवंश के संरक्षण से संबंधित प्रमुख अवरोधः

- पहले ब्यांत पर अधिक उम्र और दो ब्यांतों के बीच अधिक अंतराल
- अनुवांशिक रूप से उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म की उपलब्धता में कमी
- कम दूध उत्पादकता
- अच्छे आहार तथा चारे का पर्याप्त मात्रा में न होना
- पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं सहित पशुधन सेवाएं मुहैया करने में संपर्कों में कमी
- नस्ल—सुधार तथा देसी पशुओं के संर<mark>क्षण से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल</mark> विभिन्नल एजेंसियों के अलग—थलग प्रयास



- नस्ल—सुधार पर देसी पशुओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में शामिल गौशालाओं, धार्मिक मठों तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सीमित वित्तीय सहयोग
- पंचगव्य जैसे प्रलेखित आईटीके के वैज्ञानिक आधार को समझने और उसे मान्यता देने के प्रयासों में कमी

स्वदेशी गोवंश के सुधार को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने राज्य कार्यान्व्यन एजेंसी जैसे पशुधन विकास बोर्डों के माध्यम से एक "राष्ट्रीय गौकुल मिशन" प्रारंभ कर दिया है जिसके लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में रूपये 500.00 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इस स्कीम के तहत बड़े शहरों के पास स्वदेशी गौ नस्ल केंद्रों की स्थापना जैसे "गौकुल ग्राम", संरक्षण के लिए सांड़ मातृ फार्मों का सुदृढ़ीकरण, फील्ड प्रदर्शन रिकार्डिंग, सन्तित चयन, प्रजनक समितियों "गौपालन संघ" की स्थापना, गुणवत्ता युक्त जननसामग्री का वितरण, किसानों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार (गोपाल रत्न) तथा प्रजनक समितियां (कामधेनु) आदि सम्मिलित होंगे।

स्वदेशी गोवंश के लाभ जैसे अनुकूलनशीलताए, रोग प्रतिरोध और दूध विशेषताओं आदि के हेतू माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 86 वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान इसके संरक्षण तथा इनकी दूध उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए एक अनुवर्तित रूप में, मुद्दों पर विचार करने के लिए दूध उत्पादकता में सुधार तथा स्वदेशी पशु जर्मप्लाज्म से संबंधित मुद्दों पर विचार—विमर्श करने, चिन्हांकित विषयों में हुई वैज्ञानिक प्रगति के मूल्यांकन पर चर्चा तथा स्वदेशी पशुओं की दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने हेतु रोड—मैप तैयार करने के लिए "स्वदेशी पशुओं की दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु रणनीति" पर विशेषज्ञों तथा अन्य सहयोगियों के लिए एक दिवसीय परस्पर—परामर्श बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर), करनाल, केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), मेरठ तथा राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अकादमी (एनएवीएस) के माध्यम से संयुक्त रूप से 20 अक्तूबर, 2014 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। परस्पर—संवाद की इस बैठक में प्रौद्योगिकी विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु नीतियों, कानूनों तथा संस्थागत सुधार हेतु उपयुक्त परिवर्तन सुझाने के लिए एक प्लेटफार्म मिल सकेगा।

डा. के.एम.एल. पाठक उपमहानिदेशक पशु विज्ञान एवम् अध्यक्ष, आयोजन समिति pathakkml@yahoo.co.in















कांकरेज साहिवाल

गिर

लालसिंधी

थारपरकर

राठी

खिल्लर



ICAR-NAVS Expert Consultation Meet

on



"Strategies for Enhancing Milk Productivity of Indigenous Cattle"

October 20, 2014 (Monday)

CONCEPT

Our country has about 6 lac villages which are home to 70% of human population where cattle husbandry has always been a part of social and cultural heritage. Amongst various categories of livestock keepers the marginal, small and semi-medium farmers house about 89% of cattle population. The indigenous cattle population have been utilized for providing milk, milk products, draft power, bio-fertilizer, bio-fuel, producing bio-molecules and other products beneficial for human health besides being a source of sustained livelihood for landless and resource poor farmers.

As per XVIII Livestock census (2007), India has about 199 million cattle population which includes 166 million (83%) indigenous and 33 million (17%) crossbred and exotic cattle. Of this large population, only 23.14 million heads (11.62%) of indigenous cattle have been so far described and categorised into 44 different populations including 37 distinct and registered breeds. Indigenous cattle breeds are generally classified on the basis of their utility as milch breeds (Sahiwal, Red Sindhi, Gir and Rathi), draft breeds (Hallikar, Khillar, Nagauri, Kangayam, Red Kandhari etc.) and dual (milch and draft) purpose breeds (Tharparkar, Hariana, Kankrej, Deoni, Ongole, Dangi, Kenkatha etc). These unique breeds have been developed through dedicated efforts of livestock keepers, pastoralists and other stake-holders over a period of thousands of years.

During last few decades, the distinct biodiversity of our cattle breeds has been diluted due to changing breeding policies and adoption of a few improver breeds. Current milk production from indigenous cattle is only 2.36 kg/day at the national level. Even then the fact remains that indigenous cattle contribute significantly to the estimated (2013-14) national pool of 132.43 million tonnes of milk. Experiments conducted at various research institutes during last decade have demonstrated that many of these breeds have the genetic potential to produce 2000-3000 litres of milk in a lactation of 305 days. Since, majority of the states have draft type cattle breeds, a little improvement in their productivity will also contribute to increase in total milk production of the country.

Conservation of indigenous germplasm is equally important in light of the declining numbers over the years due to inconsistent breeding policies and consumer preference for a few breeds. Our country possesses a good infrastructure of various agencies involved in cattle improvement programme. We have more than 4000 goshalas which maintain about 20 lakh indigenous cows. In addition to 161 cattle breeding farms, 54 semen production centres, the country also processes 191 frozen semen banks, 77,765 Al centres, many veterinary hospitals/polyclinics, and dispensaries. Most of the states have animal husbandry departments and livestock development boards. Other stakeholders like NGOs, breed associations, farmer groups and pastoralists are also contributing towards breeding and conservation of indigenous cattle breeds.















Kankrei

Sahiwal

Gir

Red Sindhi

Tharparkar

Rathi

Khillar

Many of these goshalas with their own resources have been contributing towards conservation of Indian cattle breeds through proper breeding plans. These are also the treasure-houses of our ancient traditional knowledge related to cattle husbandry practices. have which demonstrated value addition through utilization of other by-products like dung, urine, horns etc in addition to milk and milk product. Unfortunately, many of these goshalas are still not well maintained in the ideal state and need financial and technical support.

Major constraints for breed improvement and conservation of indigenous cattle are:

- Higher age at first calving and inter calving period
- Insufficient availability of genetically superior germplasm
- Poor milk productivity
- Insufficient availability of quality feed and fodder
- Poor linkages for delivery of livestock services including veterinary and AI services
- Isolated efforts by different agencies involved in programmes related to breed improvement and conservation
- Limited financial support to goshalas, religious muths and other NGOs involved in the process of breed improvement and conservation
- Limited efforts to understand and validate scientific basis of documented ITKs like panchgavya

With the view to improve indigenous cattle, the Government of India has launched "Rashtriya Gokul Mission" through the State Implementing Agency viz. Livestock Development Boards for which Rs. 500.00 crores have been allocated during the XII Five Year Plan. The scheme will cover establishment of indigenous cattle centres viz. "Gokul Gram" near metropolitan cities, strengthen bull mother farms for conservation, field performance recording, pedigree selection, establishing breeders society "Gopalan Sangh", distribution of quality germplasm, incentives and awards to farmers (Gopal Ratan) and Breeders' Societies (Kamdhenu).

Recalling the advantages of indigenous cattle rearing in terms of its adaptability, disease resistance and milk attributes, etc. the Hon'ble Prime Minister during the 86th Foundation Day Celebration of ICAR emphasized the need for its conservation and desired that all attempts be made for enhancing its milk productivity potential. Hence, as a follow up, to deliberate the issues concerning both improvement of milk productivity and conservation of indigenous cattle germplasm, scientific advancement made in the identified disciplines will be discussed and assessed to prepare a road-map for enhancing milk productivity of Indigenous cattle. Accordingly, it is proposed to organize a one-day interactive Consultation Meet of experts and other stakeholders on "Strategies for Enhancing Milk Productivity of Indigenous Cattle". The programme will be jointly organized by Indian Council of Agricultural Research (ICAR) through National Bureau of Animal Genetic Resources (NBAGR), Karnal, Central Institute for Research on Cattle (CIRC), Meerut and National Academy of Veterinary Sciences (NAVS) at National Agricultural Science Centre (NASC) Complex, Dev Prakash Shastri Marg, New Delhi on October 20, 2014. The interactive meet will also provide a platform to suggest suitable changes in policies, legislation, institutions framework for technology development and capacity building.

Dr. K.M.L. Pathak
Deputy Director General (Animal Science) &
Chairman, Organizing Committee
pathakkml@yahoo.co.in

Kankrej

Sahiwal

Gir

Red Sindhi

Tharparkar

Rathi

Khillar

